दिसंबर

1. नीतीश कुमार ने अपनी 'जल-जीवन हरियाली' यात्रा के भाग के रूप में श्योहर जिले में 137 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की शुरुआत की

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्योहर में कलेक्ट्रेट ग्राउंड में 'जागरूकता सम्मेलन' के दौरान रिमोट कंट्रोल के माध्यम से 137 करोड़ रुपये की कुल 167 विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। सम्मेलन को उनकी 'जल-जीवन-हरियाली' यात्रा के चौथे चरण के भाग के रूप में आयोजित किया गया था।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 'जल-जीवन-हरियाली अभियान' पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया।

2. राज्य के लिए जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण के लिए नई नीति तैयार होगी

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से एक बिहार में जल्द ही एक नई जनसंख्या-नियंत्रण नीति होगी।
नई नीति का उद्देश्य इंजेक्शन योग्य गर्भ निरोधकों के उपयोग को बढ़ाना, पुरुषों और महिलाओं के बीच अधिक जागरूकता पैदा करना-विशेष रूप से उच्च विद्यालयों और कॉलेजों में युवा महिलाओं में जनसंख्या नियंत्रण और गर्भ निरोधकों के उपयोग के बारे में, मौजूदा चिकित्सा त्योहारों का विस्तार करना और सबसे अधिक संभावना है, प्रोत्साहन और हतोत्साहन का एक पैकेज की पेशकश शामिल है।
जुलाई 2018 में बिहार सरकार ने अंतरा नामक एक गर्भनिरोधक को पेश किया, जो तीन महीने तक गर्भधारण को अवरुद्ध कर सकता है। यह राज्य के हर स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में उपलब्ध कराया गया था, जिसमें एक सलाह दी गई थी कि गर्भनिरोधक की अंतिम खुराक के 7-10 महीने बाद गर्भधारण हो सकता है।

3. शिव दास मीणा को पीएमआरसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया

श्री शिव दास मीणा ने बिहार में पटना मेट्रो रेल परियोजना को लागू करने के लिए गठित विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड (पीएमआरसी) के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।
वह तमिलनाडु कैडर के 1989-बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) में अतिरिक्त सचिव और सीवीओ हैं, मीणा ने 14 दिसंबर, 2019 को अध्यक्ष, पीमआरसी का पदभार संभाला।

4. पटना और सात अन्य शहरों में पानी का संकट है

यहां तक कि बिहार को पीने योग्य पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, प्रस्तावित 'राज्य भूजल प्राधिकरण' को अभी तक रोशनी की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है।
2006 में, राज्य के लघु सिंचाई विभाग ने भूजल संसाधनों के दोहन को विनियमित करने के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) की तर्ज पर एक राज्य-स्तरीय प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ।
प्रस्तावित विधेयक में भूजल के बेहतर प्रबंधन और संरक्षण को सुनिश्चित करना था, जिसका स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। इसके पारित होने से न केवल जल उपयोग को विनियमित किया जा सकेगा, बल्कि भूजल को रिचार्ज करने के लिए तालाबों को खोदकर और अवरुद्ध हो रहे जल निकायों की सफाई करके इसके संरक्षण पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा ।
जहां तक पटना का संबंध है, हाल के वर्षों में जल तालिका 10 से 15 फीट नीचे चली गई है। गहरे नलकूपों के माध्यम से भरपाई की तुलना में अधिक दोहन भूजल भंडार को तेजी से समाप्त करने के लिए मजबूर कर रहा है।

5. बिहार में अपनी तरह का पहला कछुआ पुनर्वसन केंद्र

जनवरी 2020 में बिहार के भागलपुर वन प्रभाग में मीठे पानी के कछुओं के लिए अपनी तरह का पहला पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। आधा हेक्टेयर में फैला यह पुनर्वसन केंद्र एक समय में 500 कछुओं को आश्रय देने में सक्षम होगा।
पर्यावरणविदों के अनुसार, कछुए नदी में मृत कार्बनिक पदार्थों और रोगग्रस्त मछलियों की सफाई करते हैं, मछली की आबादी को शिकारियों के रूप में नियंत्रित करते हैं और जलीय पौधों और खरपतवार को नियंत्रित करते हैं। उन्हें स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के संकेतक के रूप में भी वर्णित किया गया है।
कछुए मुख्य रूप से दो कारणों से खतरे में आ गए हैं - भोजन और फलता-फूलता पालतू व्यापार।

6. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) के अध्यक्ष ब्रज बिहारी कुमार का निधन

श्री कुमार को मई 2017 में ICSSR के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) की स्थापना वर्ष 1969 में भारत सरकार द्वारा देश में सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।